आकाशवाणी केन्द्र शिमला

11.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 9:20बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए राज्य के खजाने को फिजूलखर्ची व राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा–आरडीजी को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता
- प्रधानमंत्री किसान योजना में अब तक केंद्र सरकार ने 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक राशि की वितरित
- नगर व ग्राम नियोजन विभाग ने जनसमस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के लिए जारी किए दिशानिर्देश–तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू

लोकसभा–विकसित भारत जी–राम जी

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि विकसित भारत –रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम केवल एक रोजगार कार्यक्रम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया एक व्यापक ढांचा है। कमलेश पासवान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर रोजगार प्रदान नहीं करने की स्थिति में श्रमिक को अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम में रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को कानूनी अधिकारों के रूप में संरक्षित किया गया है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूलखर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्ष के कार्यकाल में 54 हजार 2 सौ 96 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) मिला था। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में केवल 17 हजार 5 सौ 63 करोड़ रुपये आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है।

इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए गए वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से नकारते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्तायोग मे राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने का ऐलान अभी किया लेकिन तैयारी 15 वें वित्तायोग ही नहीं 12वे वित्तायोग के बाद आयोग बार–बार कह रहा है कि राजस्व अनुदान घाटे को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये केंद्र की ओर से मदद है।

लोकसभा–पीएम किसान

प्रधानमंत्री–किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक केन्द्र सरकार ने 21 किस्तों में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री–किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2019 में किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसकी शुरूआत की थी। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष छह हजार रुपये की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान–केंद्रित डिजिटल अवसंरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ के पहुंचे।

सूचना प्रौद्योगिकी

उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में लोगों और सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है और जिला किन्नौर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह अति आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण आवश्यक और संवेदनशील सूचनाओं का दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षित डिजिटल विकल्पों का चुनाव करना, साइबर हाइजीन, आम जनता को अपने पासवर्ड की सुरक्षा और संदिग्ध लिंक्स से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमित कुमार ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के मध्यम से युवाओं और छात्रों को ऑनलाइन जानकारी की सत्यता परखने और व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है।

इग्लू

कुल्लू जिला में मनाली के नज़दीक हामटा क्षेत्र में इन दिनों इग्लू (बर्फ के घर) आकर्षण का केंद्र बने है। हामटा व् सेथन का यह इलाका एक तरह से इग्लू विलेज बन गया है । यहां पर 20 से अधिक

इग्लू बनाए गए है। समुद्रतल से लगभग 9 हज़ार फुट की ऊंचाई पर बनाए गए इग्लू पर्यटकों को आकर्षित कर रहे है तथा जहां बड़ी संख्या में सैलानी इग्लू में रात बिताने पहुँच रहे है। इग्लू में बिस्तर के साथ–साथ खाना व् चाय इत्यादि की भी व्यवस्था है।

दिशानिर्देश

नगर व ग्राम नियोजन विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनसमस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगर व ग्राम नियोजन विभाग में तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत डिविजिनल जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया तय की गई है।

और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से.....

आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान को प्रमुखता दी है।

अमर उजाला की सुर्खी है–ओपीएस बंद नहीं होगी, अपने संसाधनों से जनता के हितों की करेंगे रक्षा। दिव्य हिमाचल और दैनिक भास्कर के एक जैसे शब्द हैं–न आपीएस बंद होगी, न सैलरी–पैंशन रोकेंगे। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है–हिमाचल में बंद नहीं की जाएगी ओल्ड पैंशन स्कीम। दैनिक जागरण लिखता है–पूर्व भाजपा सरकार ने की फिजूलखर्ची। आपका फैसला का कहना है–आरडीजी बंद होने के बावजूद ओपीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं रहेंगी जारी।

''अंत में मुख्य समाचार'' एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए राज्य के खजाने को फिजूलखर्ची व राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से किया खारिज, कहा–आरडीजी को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता
- प्रधानमंत्री किसान योजना में अब तक केंद्र सरकार ने 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रूपये से अधिक राशि की वितरित
- नगर व ग्राम नियोजन विभाग ने जनसमस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के लिए जारी किए दिशानिर्देश–तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू